संदर्भ की शर्तों में बदलाव के साथ कूटनीति

द हिन्दू

पेपर-II
(अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

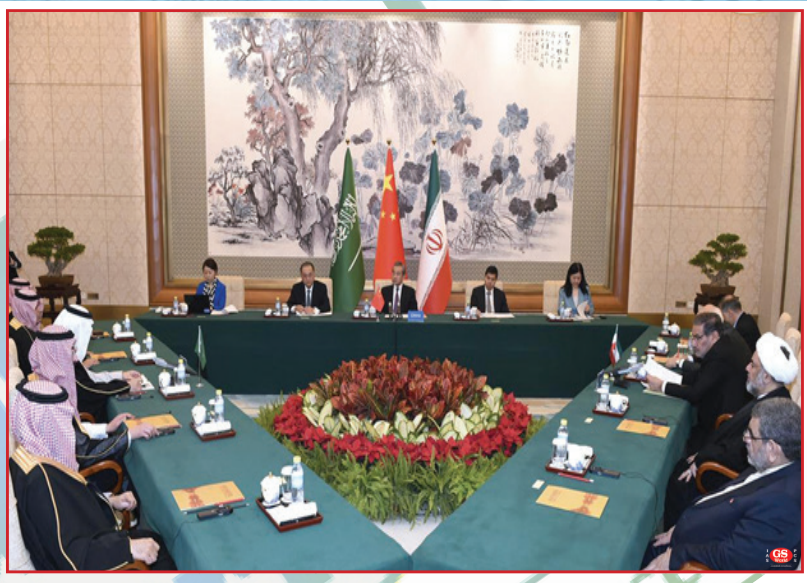

मध्यस्थता शायद ही कभी एक सहज कार्य होता है, अक्सर यह व्यक्तियों या संगठनों के विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच मिलन बिंदु की तलाश के शांत प्रयासों से पहले होता है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में **'विवादों के प्रशांत निपटान'** के माध्यम से आता है। लेकिन कानूनी दृष्टि से गुड ऑफिसेस और आर्बिट्रेशन से अलग है। इसका एक अच्छा उदाहरण हाल ही में वैश्विक मंच पर देखने को मिला। प्रेरणा के सवाल पर बहस हो सकती है।

ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता

ईरान, सऊदी अरब और चीन द्वारा 10 मार्च, 2023 को एक संयुक्त बयान में, तीनों देशों ने घोषणा की कि सऊदी अरब साम्राज्य और इस्लामिक गणराज्य ईरान के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें उनके बीच राजनयिक संबंधों की बहाली और दो महीने के अवधि के भीतर अपने दूतावासों और मिशनों को फिर से खोलना शामिल है। समझौते ने राज्यों की संप्रभुता, राज्यों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप के लिए उनके सम्मान की पुष्टि की और कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्री इसे लागू करने के लिए मिलेंगे, अपने राजदूतों की वापसी की व्यवस्था करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली शामखानी, ईरान में सर्वोच्च नेता के कार्यालय से हैं और समझौते को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।

समझौता एवं उपलब्धि

11 मार्च को एक ईरानी अखबार में एक टिप्पणी ने इस घटना को **'एक समझौता और सात उपलब्धियां'** के रूप में चित्रित किया–

1. इसने बाद को तेहरान की बातचीत में शामिल होने की इच्छा के रूप में सूचीबद्ध किया।
2. ईरान को अलग-थलग करने की अमेरिका की कोशिश नाकाम
3. इस्लामिक देशों के गठबंधन को मजबूत करना।
4. इस समझौते के खिलाफ इजरायल के प्रयासों की विफलता।

5. ईरानी जनता को यह दिखाने की, अमेरिकी प्रयास की विफलता कि उसके पास अमेरिका के साथ संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

6. पश्चिम एशियाई संबंधों में बीजिंग की सफल प्रविष्टि।

7. 'सत्ता परिवर्तन' के सपनों की विफलता।

अमेरिकी और इजरायली प्रतिक्रियाएँ

अछूते आश्चर्य के अलावा अमेरिकी प्रतिक्रियाओं ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में शर्तों के संदर्भ में परिवर्तन को प्रतिबिंबित किया। समान रूप से हैरान इस्राइल था, इस क्षेत्र का अन्य प्रमुख खिलाड़ी जिसने इसे ईरान के खिलाफ एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाने के प्रयास के लिए एक घातक झटका के रूप में देखा। एक टिप्पणीकार ने कहा 'चीन सऊदी अरब को ईरान के साथ ऐसे समय में लाया जब इजराइल को उम्मीद थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका उसे सऊदी अरब के साथ लाएगा'। हेनरी किसिंजर ने द वाशिंगटन पोस्ट के डेविड इग्नाटियस को बताया कि 'मैं इसे मध्य पूर्व में रणनीतिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखता हूँ। सऊदी अब अमेरिका के खिलाफ चीन के साथ अपनी सुरक्षा को संतुलित कर रहा हैं।'

आरोन मिलर, जिन्होंने मध्य पूर्व में विदेश विभाग के सलाहकार के रूप में लंबे समय तक सेवा की, ने कहा कि विकास 'दिखाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव और क्षेत्र में विश्वसनीयता कम हो गई है और एक नए प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संरेखण हो रहा है जिसने सशक्त रूस और चीन दोनों को नया प्रभाव और दर्जा दिया।

पृष्ठभूमि

घटना की पृष्ठभूमि उल्लेखनीय है। तेहरान, रियाद और अबू धाबी के बीच और आम तौर पर यमन और सीरिया के संबंध में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के भीतर विकसित हुए तनाव को कम करने के लिए 2016 की शुरुआत से द्विपक्षीय प्रयास चल रहे हैं। कुवैत के अमीर और ओमान के सुल्तान ने ऐसे कदम उठाए जिनका ईरान ने जवाब दिया। फरवरी में बगदाद और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की चीन यात्रा के दौरान भी वार्ता हुई थी। सऊदी अरब (केएसए) और संयुक्त अरब अमीरात के साम्राज्य में शिपिंग और ऊर्जा सुविधाओं पर हमलों और चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में चिंतित थे। ये सब मिलकर 'टकराव की अग्रिम पंक्ति पर होने के जोखिमों को इस समझौते तक ले आए'।

दिसंबर 2022 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा में भी उन्होंने पहले चाइना- अरब स्टेट्स समिट और चाइना-जीसीसी समिट में भाग लिया। उनके संबोधन का विषय था 'पिछली उपलब्धियों पर निर्माण और संयुक्त रूप से चीन जीसीसी संबंधों का एक उज्जवल भविष्य बनाना'। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन और जीसीसी को आम सुरक्षा के लिए भागीदार होना चाहिए, चीन अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए जीसीसी देशों का दृढ़ता से समर्थन करना जारी रखेगा और क्षेत्र के देशों द्वारा बातचीत और परामर्श के माध्यम से मतभेदों को हल करने और खाड़ी सुरक्षा बनाने के प्रयासों का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा, चीन क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने के संयुक्त प्रयास में वैश्विक सुरक्षा पहल (जीएसआई) में जीसीसी देशों की भागीदारी का स्वागत करता है।

भाषण ने पाँच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर दिया है :-

1. ऊर्जा सहयोग
2. वित्त और निवेश सहयोग
3. नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
4. एयरोस्पेस सहयोग
5. चीनी भाषा और सांस्कृतिक सहयोग

2023-2027 के लिए कार्य योजना पर सहमति बनी। विशिष्ट समझौतों के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते और कुछ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसने कहा कि दोनों ने 'एक दूसरे के मूल हितों' का समर्थन किया। चीनी पक्ष ने चीनी हज और उमराह तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। बयान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के संबंध में संयुक्त सहयोग को गहरा करने और सऊदी मेगा-प्रोजेक्ट में चीनी विशेषज्ञता को आकर्षित करने के महत्व पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने केएसए के विजन 2030 और बी. आरआई के बीच 'एक सामंजस्यपूर्ण योजना' पर हस्ताक्षर किए। यह बताया गया है कि बीजिंग में एक चीन-जीसीसी शिखर सम्मेलन निर्धारित किया जा रहा है।

भारतीय स्टैंड

इस घटनाक्रम पर भारत की प्रतिक्रिया संयमित रही है। ऐतिहासिक संबंधों के अलावा, यह क्षेत्र भारत के निकटवर्ती पड़ोस में और इसके सुरक्षा मापदंडों के भीतर है। यह हाइड्रोकार्बन आयात और तेजी से बढ़ते निवेश का प्रमुख स्रोत है। यह परियोजनाओं सहित एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार होने के अलावा जनशक्ति निर्यात के लिए भी एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। भारतीय आधिकारिक नीति ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने तथा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय विवादों में शामिल होने से बचने पर ध्यान केंद्रित किया है। इन प्राथमिकताओं को देखते हुए, भारत ने सहकारी सुरक्षाजलमार्गों और नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करने के अलावा वैकल्पिक सुरक्षा ढांचे में सट्टेबाजी के उपक्रमों से सचेत रूप से परहेज किया है। चीन की आर्थिक और सैन्य क्षमता के बिना इस क्षेत्र को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं देखा जाना चाहिए और न ही भारत को उन लोगों के लिए खुद को सरोगेट मानना चाहिए, जो कम से कम इस समय के लिए सत्ता के खेल में क्षणिक स्नेह के लिए मात खा गए हैं।

केन्द्रीय बिंदु

चीन के मध्यस्थता प्रयासों के परिणामस्वरूप सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हुई है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बदलती गतिशीलता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

मध्यस्थता क्या है?

मध्यस्थता दो पक्षों के बीच मतभेदों को सुलझाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, और यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन की हालिया मध्यस्थता प्रयास हॉल ही में चर्चा में है जिसके कारण सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हुई।

यू एन चार्टर का अनुच्छेद 33

चार्टर के अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि कोई भी विवाद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल सकता है, उसे पहले बातचीत, मध्यस्थता या अन्य शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए और कहा गया है कि परिषद पार्टियों को अपने विवाद समाधान के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करने के लिए कह सकती है।

सऊदी अरब तथा ईरान के बीच राजयनिक संबंध

लगभग 7 साल पहले 2016 में दोनों ने अपने राजयनिक संबंध तोड़ लिए थे, और दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि अरब प्रायद्वीप में युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। दरअसल 2016 में सऊदी अरब में प्रमुख शिया धर्मगुरु निम्र अल-निम्र सहित 47 लोगों को आतंकवाद के आरोपों में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद तेहरान में प्रदर्शनकारी सऊदी अरब के दूतावास में घुस गए। इस घटना के बाद सऊदी अरब और ईरान के राजनयिक रिश्ते खत्म हो गए थे।

शिया-सुन्नी की विचारधारा का है अंतर

सऊदी अरब और ईरान में दो तरह के मुसलमानों की बहुलता है। इनमें ईरान शिया जबकि सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिमों की बहुलता वाला देश है। दुनिया में अधिकतर मुसलमान सुन्नी हैं और वे खुद को शिया की तुलना में बेहतर मानते हैं। इसलिए इन दोनों देशों में व्यावहारिक संबंध उतने मधुर नहीं रहे, अब जबकि दोनों के प्रतिनिधियों के बीच चीन (China) ने मध्यस्थता कराई है तो इनके आपसी संबंध सुधारने के संकेत हैं।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित में से कौन 'खाड़ी सहयोग परिषद' का सदस्य नहीं है?

(a) ईरान

(b) सऊदी अरब

(c) ओमान

(d) कुवैत

Que. Which of the following is not a member of 'Gulf Cooperation Council'?

(a) Iran

(b) Saudi Arabia

(c) Oman

(d) Kuwait

उत्तर : A

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : चीन की मध्यस्थता ने सऊदी अरब और ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में कामयाब रहा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसके महत्त्व एवं प्रभावों पर प्रकाश डालिए। इस घटनाक्रम से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

का दृष्टिकोण :-

- चीन की मध्यस्थता ने सऊदी अरब और ईरान के बीच हुए समझौते का विवरण दीजिये।
- अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसके महत्व एवं प्रभावों की चर्चा कीजिये।
- इस समझौते का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइये।
- संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।